जनसत्ता

दागियों का दबदबा

आपराधिक छवि वालों को राजनीति से दूर रखने को लेकर पिछले कई सालों से आवाजें उठ रही हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भी आपराधिक रिकॉर्ड वाले जनप्रतिनिधियों को लेकर समय-समय पर गंभीर चिंता जताई है, लेकिन इस समस्या से निपटने की जिम्मेदारी संसद को ही सौंप दी। दागियों के मामलों की सुनवाई करते हुए पिछले साल एक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि आपराधिक छवि वालों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए संसद ही कानून बनाए। शीर्ष अदालत के इस फैसले से यह उम्मीद बंधी थी कि राजनीतिक दल इस गंभीर और संवेदनशील मामले को प्राथमिकता में रखेंगे और ऐसे कानून बनाए जाएंगे, ताकि चुनावों में अपराध की पृष्ठभूमि वालों को टिकट न मिल पाए। लेकिन ऐसा कुछ होता दिखा नहीं। उलटे, सारे दलों ने ऐसे लोगों को टिकट देने में कमी नहीं की। नतीजा यह है कि इस बार नई लोकसभा में दागी जनप्रतिनिधियों की संख्या पिछली बार के मुकाबले काफी ज्यादा है। जाहिर है, राजनीतिक दल ही इस दुष्प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं। यह गंभीर चिंता का विषय है।

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की ताजा रिपोर्ट बता रही है कि इस बार लोकसभा के लिए चुने गए नए सांसदों में तैंतालीस फीसद ऐसे हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं। यानी लोकसभा के कुल सदस्यों में से आधे से सिर्फ सात फीसद कम। दागी जनप्रतिनिधियों की यह संख्या मामूली नहीं है। यह इतना बड़ा आंकड़ा है जो यह सोचने पर मजबूर कर रहा है कि अगर दागियों को चुनाव लड़ने से रोकने के ठोस प्रयास जल्द ही नहीं किए गए तो कहीं हमारी संसद दागियों के गढ़ में तो तब्दील नहीं हो जाएगी! चिंता की बात यह है कि राजनीति को साफ-सुथरा बनाने के लिए हम जितनी गंभीरता से बात और प्रयास कर रहे हैं, दागियों की संख्या कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। इस बार नई लोकसभा में सबसे ज्यादा एक सौ सोलह यानी उनतालीस फीसद दागी सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। इसी तरह कांग्रेस के उनतीस, जनता दल (एकी) के तेरह, द्रमुक के दस और तृणमूल कांग्रेस के नौ सांसद दागदार छवि के हैं। इनमें उनतीस फीसद मामले हत्या, हत्या की कोशिश और बलात्कार जैसे जघन्य अपराध वाले हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि 2009 के मुकाबले 2019 में गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड वाले सांसदों की संख्या में एक सौ नौ फीसद का इजाफा हुआ है। अगर विधानसभाओं की बात करें तो इस बार ओड़ीशा विधानसभा में भी दागी जनप्रतिनिधियों की संख्या पिछली बार के मुकाबले बढ़ी है। और आंध्र प्रदेश में एक सौ चौहत्तर में से एक सौ इक्यावन विधायकों पर कोई न कोई मामला दर्ज है।

दूसरी ओर, बहुजन समाज पार्टी के एक नवनिर्वाचित सांसद को बलात्कार के एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी से किसी प्रकार का संरक्षण प्रदान करने से इनकार कर दिया है। ऐसा कर अदालत ने यह संदेश दिया है कि वह जघन्य अपराधों में शामिल किसी जनप्रतिनिधि के मामले में कोई नरमी नहीं बरतने वाली है। कानून अपना काम करेगा। अब सवाल राजनीतिक दलों के सामने है कि वे ऐसे मामलों में क्या रुख अपनाते हैं। जिन विधायकों पर पहले से ही कई मामले दर्ज हों, उन्हें सिर्फ जीतने के लिए चुनाव लड़ाना संसद को अपराधियों का गढ़ बनाना है और यह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। सवाल है कि जब हमारे जनप्रतिनिधि हत्या, हत्या की कोशिश, अपहरण, बलात्कार जैसे संगीन अपराधों में लिप्त रहने वाले लोग होंगे तो उनसे देश किस तरह के भविष्य की उम्मीद करेगा।

शराब का कहर

उत्तर प्रदेश में बाराबंकी के रानीगंज गांव में जहरीली शराब के सेवन के बाद चौदह लोगों के मारे जाने की घटना ने एक बार फिर अवैध रूप से चल रहे नशे के कारोबार पर रोक लगाने से जुड़े इंतजामों, इससे संबंधित नियम-कायदों या कानूनों पर अमल सुनिश्चित कराने पर सवालिया निशान लगाया है। खासतौर पर इसलिए भी कि शराब का कारोबार आमतौर पर प्रशासन और संबंधित महकमों की निगरानी में संचालित होता है। इसके बावजूद हर कुछ समय बाद नकली और जहरीली शराब पीकर काफी संख्या में लोगों के मारे जाने की खबरें आती रहती हैं। रानीगंज में जिस शराब को पीने से दर्जन भर से ज्यादा लोगों की जान चली गई, वह बाकायदा आबकारी विभाग के पंजीकृत विक्रेता के यहां से खरीदी गई थी। यानी सरकार या प्रशासन की निगरानी के तहत संचालित शराब की दुकान से ऐसी शराब बेची जा रही थी, जो किसी की जान ले सकती थी। सवाल है कि रानीगंज इलाके के उस शराब विक्रेता के भीतर यह हिम्मत कहां से आई कि वह पंजीकृत दुकान से ही नकली और जहरीली शराब का धंधा भी चलाए?

आबकारी विभाग की यह जिम्मेदारी है कि वह समय-समय पर पंजीकृत विक्रेताओं के यहां इस बात की जांच कराए कि वहां किस गुणवत्ता की शराब बेची जा रही है और कहीं वहां स्थानीय स्तर पर बनाई जाने वाली नकली शराब तो नहीं बेची जा रही! लेकिन इसके बावजूद रानीगंज की दुकान की शराब पीकर लोगों की मौत हुई तो इसके लिए किसकी जिम्मेदारी बनती है? क्या निगरानी में लापरवाही बरतने वाले आबकारी महकमे के अफसरों को भी कठघरे में खड़ा किया जाएगा? जिस गांव में यह त्रासदी सामने आई है, वहां गांव के लोगों का आरोप है कि शराब की पंजीकृत दुकान का मालिक ही अलग से नकली शराब बनाने की एक गैरकानूनी फैक्ट्री भी चलाता है। नकली शराब भी उसी सरकारी ठेके वाली दुकान पर बेची जाती है। जाहिर है, इतने लोगों की मौत का जिम्मेदार अकेले जहरीली शराब लोगों को बेच देने वाला ही नहीं है, बल्कि उसे गैरकानूनी धंधे की छूट देने वाले भी हैं। जब मामले ने तूल पकड़ लिया तब जाकर उस दुकान के एक सेल्समैन को गिरफ्तार किया गया और फैक्ट्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन इस तरह की कार्रवाइयों के बावजूद ऐसा क्यों है कि हर कुछ समय बाद फिर नकली और जहरीली शराब पीकर लोगों के मरने कोई घटना सामने आ जाती है।

गौरतलब है कि इसी साल फरवरी में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चार जिलों में जहरीली शराब पीने से करीब सवा सौ लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा, फरवरी में ही असम में ठीक इसी वजह से लगभग डेढ़ सौ लोग मारे गए थे। मुश्किल यह है कि समूचे देश में इस मसले पर सरकारों की नींद तभी खुलती है, जब ऐसी किसी घटना में बड़ी तादाद में लोगों की जान जाती है। अव्वल तो दिखावे की रस्मों के अलावा सरकार की ओर से ऐसी कोई पहल नहीं दिखती कि लोग शराब पीने की आदत की ओर न बढ़ें। कई बार निजी पसंद का हवाला देकर भी लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। जबकि शराब की आदत से होने वाले आर्थिक-सांस्कृतिक और सेहत से जुड़े तमाम नुकसान उठाने वालों से लेकर जहरीली शराब पीकर मरने वालों तक में आमतौर पर गरीब तबके के ही लोग होते हैं। तो क्या इसी वजह से शराब से पैदा होने वाली सामाजिक समस्याओं और यहां तक कि मौतों तक के मामले को कोई बड़ी और गंभीर समस्या के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता?

कल्पमेधा

सामान्य नेता लोगों को उस जगह ले जाते हैं जहां वे जाना चाहते हैं। महान नेता वहां ले जाते हैं जहां लोग जाना नहीं चाहते, फिर भी जाने की आशा रखते हैं।

-रोजलिन कार्टर

हिंसा की कूटनीति में फंसा ईरान

ब्रह्मदीप अलूने

अमेरिका और ईरान के बीच ताजा तनाव को लेकर सऊदी अरब के विदेश मंत्री अदेल अल-जुबैर ने कहा है कि सऊदी अरब इस इलाके में किसी भी तरह का संघर्ष नहीं चाहता। जबकि वास्तव में ईरान को अस्थिर करने में सऊदी अरब अग्रणी है। सऊदी अरब और ईरान का धार्मिक-वैचारिक टकराव मध्य-पूर्व के कई देशों को प्रभावित करता रहा है।

अंतरराष्ट्रीय राजनीति में 'हिंसा की कूटनीति' का उपयोग महाशक्तियां बदले की नीति के तौर पर करती रही हैं। इस आक्रामक नीति का एकमात्र लक्ष्य दुश्मन पर विजय पाना रहा है। इसलिए प्रतिद्वंद्वी राष्ट्र पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए युद्धोन्माद, आर्थिक प्रतिबंध, खतरनाक हथियारों की तैनाती जैसी कोशिशें की जाती हैं, ताकि वह राष्ट्र अस्थिरता की ओर बढ़ जाए और गहरे दबाव में महाशक्तियों के आगे झुक जाए। दरअसल, मध्य-पूर्व अंतरराष्ट्रीय राजनीति का ऐसा केंद्र है जहां महाशक्तियां अपने आर्थिक लाभ के लिए युद्धोन्माद की स्थितियां पैदा करती रही हैं। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद मध्य-पूर्व की तेल कूटनीति ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति को काफी प्रभावित किया है। इसी तेल के चलते ईरान की खाई जैसी मरुभूमि भी आज वरदान बन गई है। लेकिन वहीं इस इलाके की यह विशेषता मध्य-पूर्व की अशांति का कारण भी बन गई है। हिंसा और अशांति से अभिशप्त मध्य-पूर्व को एक बार फिर युद्ध की ओर धकेला जा रहा है। इस बार अमेरिका का निशाना एक स्थापित राष्ट्र ईरान है जिसकी बर्बादी दुनिया में मानवीय त्रासदी का कारण बन कर आतंकवाद को मजबूत कर सकती है।

अमेरिका ने ईरान पर चोरी-छिपे परमाणु कार्यक्रम चलाने का आरोप लगा कर न केवल उससे अपनी संधि को खत्म कर दिया है, बल्कि हाल ही में भारत और चीन जैसे चुनिंदा देशों पर से भी ईरान से तेल खरीदने की छूट वापस लेकर ईरान की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने की अपनी निर्णायक चाल चल दी है। अमेरिका के इस कदम से ईरान तेल का निर्यात नहीं कर पा रहा है और उसकी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ने लगा है। आर्थिक के साथ सामरिक दबाव बढ़ाने के लिए ट्रंप ने ईरान के कड़े प्रतिद्वंद्वी सऊदी अरब के साथ ट्रंप ने आठ अरब डॉलर के हथियार सौदे को मंजूरी दे दी है। इन हथियारों में अत्याधुनिक युद्ध सामग्री और आधुनिक बम शामिल हैं। इसके साथ ही अमेरिका ने अपने जंगी जहाज को समंदर में तैनात कर दिया है। मध्य-पूर्व के इराक जैसे देश से अमेरिका के नागरिकों को वापस लौटने को कह दिया गया है। अमेरिका के इस कदम से मध्य-पूर्व में पहले से ही जो अस्थिरता बनी हुई है, वह युद्ध की प्रबल आशंका में बदल गई है।

ईरान को लेकर अमेरिकी नीति में आक्रामकता का एक प्रमुख कारण ट्रंप का कथित इजराइल प्रेम भी रहा है। इजराइल के अस्तित्व को पश्चिम एशिया में नकारने वाला पठारी, पहाड़ी और मरुस्थलीय ईरान मध्य-पूर्व का ऐसा आक्रामक खिलाड़ी है जिसका खौफ अरब के सुन्नी देशों, इजराइल और अमेरिका को भी परेशान करता रहा है। शिया बहुल ईरान धार्मिक कारणों से सऊदी अरब के निशाने पर है, सामरिक दृष्टि से वह इजराइल का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है, जबकि इजराइली प्रेम में डूबे अमेरिका के लिए ईरान शैतान की धुरी है।

ईरान को दबाने की कोशिशों में साल 2018 में इजराइल को तब सफलता मिली जब ईरान के गोपनीय परमाणु हथियार कार्यक्रम 'प्रोजेक्ट अमाद' की हकीकत को बेहद सनसनीखेज तरीके से दुनिया के सामने लाकर इजराइल ने रणनीतिक दांव खेला। ईरान के मध्य एशिया में बढ़ते प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए इजराइल ने अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद के जरिए ईरान के परमाणु कार्यक्रम में सेंध लगा कर दुनिया को हैरान कर दिया था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पिछले साल दावा किया कि उनके पास तेहरान के एक गुप्त ठिकाने से इजराइली खुफिया विभाग को मिली डेटा की 'कॉपियां' हैं। इनमें पचपन हजार पन्नों के सबूत के साथ 183 सीडी और फाइलें हैं। नेतन्याहू ने यह दावा किया था कि ईरान परमाणु समझौते को ठेंगा दिखा कर गुपचुप तरीके से परमाणु हथियारों का जखीरा बनाने की ओर अग्रसर है। इजराइल के इस खुलासे के बाद ट्रंप ने बेहद आक्रामक कदम उठाने के संकेत दे डाले। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के साथ साल 2015 में हुए परमाणु समझौते से अमेरिका को अलग करने की घोषणा कर इसे अप्रासंगिक और बेकार बता कर दुनिया के सामने एक नया कूटनीतिक संकट खड़ा कर दिया। ट्रंप यहीं नहीं रुके। उन्होंने ईरान के साथ हुए समझौते के बाद आर्थिक प्रतिबंधों में जो रियायतें दी गई थीं, उसे पुनः लागू कर दिया।

इसके पहले साल 2015 में ओबामा प्रशासन में हुए एक समझौते के तहत ईरान पर हथियार खरीदने पर पांच साल तक प्रतिबंध लगाया गया था। इसके साथ ही मिसाइल प्रतिबंधों की समय सीमा आठ साल तय की गई थी। इसके बदले में ईरान ने अपने

परमाणु कार्यक्रम का बड़ा हिस्सा बंद कर दिया था और बचे हुए हिस्से की निगरानी अंतरराष्ट्रीय निरीक्षकों से कराने पर राजी हो गया था। जनवरी 2016 में शुरू हुए इस समझौते को 'ज्वाइंट एंड कंप्लीट एक्शन प्लान' का नाम दिया गया था। इस समझौते पर जर्मनी, चीन, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस के साथ तेहरान ने हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटाने के बदले उसे परमाणु कार्यक्रमों पर नियंत्रण लगाना है। इस प्रकार ईरान के साथ इस समझौते में अन्य वैश्विक शक्तियां भी शामिल हुई थीं और इस परमाणु समझौते को मध्य-पूर्व में शांति स्थापना की दिशा में उठाया गया एक महत्त्वपूर्ण कदम माना गया था।

दूसरी ओर सऊदी अरब की इस्लामिक देशों का सर्वमान्य नेतृत्व कहलाने की आकांक्षा ने भी मध्य-पूर्व की शांति को संकट में डाला है। अमेरिका और ईरान के बीच ताजा तनाव को लेकर सऊदी अरब के विदेश मंत्री अदेल अल-जुबैर ने कहा है कि सऊदी अरब इस इलाके में किसी भी तरह का संघर्ष नहीं चाहता। जबकि वास्तव में ईरान को अस्थिर करने में सऊदी अरब अग्रणी है। सऊदी अरब और ईरान का धार्मिक-वैचारिक टकराव मध्य-पूर्व के कई देशों को प्रभावित करता रहा है।

अरब का एक देश यमन गृहयुद्ध से जूझ रहा है। वहां पर सऊदी अरब के नेतृत्व में एक अंतरराष्ट्रीय गठबंधन की सेना है जो हूथी विद्रोहियों से मुकाबला कर रही है। सऊदी नेतृत्व को यह लगता है कि हूथी विद्रोहियों को ईरान से हथियारों की मदद मिल रही है। सीरिया में जारी गृहयुद्ध में ईरान राष्ट्रपति बशर अल-असद का समर्थन कर रहा है। बशर को रूस का समर्थन हासिल है। पश्चिम एशिया के एक और देश लेबनान में अस्थिरता है और यहां पर ईरान समर्थित शिया मिलिशिया समूह हिजबुल्ला का प्रभाव सऊदी अरब के लिए जानलेवा है। यमन, सीरिया और लेबनान में ईरान का सामरिक मित्र रूस है और इसीलिए मध्य-पूर्व में नियंत्रण स्थपित रखने के लिए महाशक्तियां आमने-सामने हैं।

इस घटनाक्रम के साथ यह बेहद दिलचस्प है कि मुसलिम दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन इजराइल को लेकर सऊदी अरब के रुख में आश्चर्यजनक परिवर्तन आया है और उसके नेता कई मंचों पर एक दूसरे से रू-ब-रू भी हुए हैं। इसका प्रमुख कारण इजराइल और ईरान के बीच कड़ी दुश्मनी ही है। इजराइली सेना प्रमुख तो यह भी कह चुके हैं कि मध्य-

बेटियों की जगह

अनीता यादव

कुछ समय पहले मेरी एक विद्यार्थी ने मुझसे कक्षा से बाहर चल कर एकांत में अपनी बात सुन लेने की गुजारिश की। उसने बताया कि वह कॉलेज की पढ़ाई के साथ-साथ एनसीसी में भी है और इसका 'सी' सर्टिफिकेट भी अर्जित किया हुआ है, जो आगे चल कर नौकरी में सहायक होगा। घर पर वह दो शिफ्ट में ट्यूशन भी पढ़ाती है ताकि जेब खर्च के लिए परिवार पर कोई आर्थिक दबाव न पड़े। साथ ही घर के कामों में मां का हाथ बंटाती है। इसके बावजूद वह बात-बात पर पराया धन होने के ताने सुनती है। निठल्ले और उम्र में छोटे होने के बावजूद मात्र लड़का होने भर से उच्चता बोध पाले भाई से लिंग भेद का शिकार ही नहीं हो रही, बल्कि पढ़ाई छुड़ा कर शादी कर देने की धमकी भी झेलती है। जबकि वह पढ़ाई पूरी कर आर्थिक रूप से स्वावलंबी होना चाहती है, ताकि किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े।

अपने ही घर और अभिभावकों के प्रति ऐसी राय रखने वाली यह अकेली लड़की नहीं है। एक अन्य छात्रा का भी यही कहना था कि उस पर नियमित कॉलेज छोड़ कर 'ओपन लर्निंग' से पढ़ाई पूरी करने का दबाव बनाया जा रहा है। उसने यह भी बताया कि सगे-संबंधियों ने परिवार से केवल इसलिए संबंध विच्छेद कर लिए कि पिताजी ने मुझे यानी बेटी को नियमित कॉलेज में प्रवेश दिला कर परिवार की नाक कटा दी है। अब पिताजी चाहते हैं कि वह कॉलेज छोड़ घर बैठ घर का कामकाज सीखे। या पढ़ना है तो 'ओपन लर्निंग' से पढ़े! अमूमन ऐसा कम ही होता है कि बच्चे अपने माता-पिता या परिवार की शिकायत किसी अध्यापक से करें।

दुनिया मेरे आगे

यहां समझना आसान है कि इन बच्चियों ने ऐसा क्यों किया! दुनिया भर की समस्याएं मां की गोद या उसके पल्लू के स्पर्श मात्र से सुलझ जाती हैं। लेकिन अगर समस्याएं उसी पल्लू से पैदा हों तो स्थिति दयनीय होती है। इससे पार पाना एक लड़की के लिए आसान नहीं! यह समझना मुश्किल नहीं है कि मुझसे बात करने से पहले वे बच्चियां जेहनी तौर पर कितनी पीड़ा से गुजरी होंगी! यह स्थिति देश की राजधानी से सटे उन कस्बों की है जो घर में रोशनी के लिए चाहे एलईडी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मन आज भी 'ढिबरी' जलाने वाली जड़ मानसिकता से ग्रस्त है। यह मानसिक दिवालियापन नहीं तो क्या है! ऐसे खोखले माता-पिता ही अपनी बेटी को शादी के वक्त समझाते हैं कि मायके से डोली और ससुराल से अर्थी उठनी चाहिए। यही तुम्हारा धर्म है। और जाने कितनी बेटियां इस खोखली सीख को पल्लू से बांध मानसिक रूप से तैयार हो जाती हैं, समय से पूर्व ही अपनी अर्थी उठवाने के लिए।

एक ओर सरकार लड़कियों के जन्म लेने और उनकी पढ़ाई और शादी के नाम पर कितनी योजनाएं बना चुकी है। हालांकि योजनाओं की जमीनी हकीकत भी दर्ज हो रही है। उनका क्या जो जन्म देकर 'पराया-धन' का तमगा लटका कर सफलता की सीढ़ियां चढ़ने से पहले ही उनके पैरों तले की जमीन छीन ले रहे हैं। उनकी यह सोच है कि बेटी पढ़-लिख गई तो हमें क्या फायदा... आखिर कमाई तो ससुराल को ही देगी! जबकि उनके काम तो 'वंश-बेल' बढ़ाने वाला बेटा ही आएगा। जब अभिभावक खुद ही बेटा-बेटी में इतना अंतर रखेंगे तो उस समाज में बेटी का रास्ता कितना कांटों भरा हो सकता है, इसे समझना मुश्किल नहीं।

समाज में दिन-प्रतिदिन घट रही घटनाएं इसका पुख्ता प्रमाण हैं कि बेटे अपने मां-बाप की कितनी सेवा या आदर कर रहे हैं। मेरे कहने का यह मतलब कतई नहीं है कि बेटों के लिए समाज में कोई बुरी भावना पनपे या उन्हें कमतर आंका जाए, बल्कि बेटियों को उचित

बड़ा अवसर

भारतीय जनता पार्टी को मिला बड़ा जनादेश एक और मौका है जब वह सुधार से जुड़े अपने वादों को हकीकत में बदल सकती है। लोकतंत्र में मिली इस बड़ी जीत का असर जब कम होगा तब अर्थव्यवस्था से जुड़ी कठिन चुनौतियां सरकार के सामने आएंगी। विशाल जनादेश देख कर हम उम्मीद कर सकते हैं कि अपने दूसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री साहसिक कदम उठा सकते हैं। लेकिन सवाल है कि क्या यह जनादेश भारत के सामने खड़ी परेशानियों जितना ही बड़ा है? तीन महीनों में दिसंबर 2018 तक आर्थिक वृद्धि दर धीमी होकर 6.6 फीसद रह गई। यह छह तिमाहियों की सबसे धीमी दर रही।

एनएसएसओ के एक कथित लीक डेटा के मुताबिक इन पांच वर्षों में बेरोजगारी पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा रही है। सरकार को रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए कई क्षेत्रों में निजी निवेश को हरी झंडी देनी होगी। उसकी बहुचर्चित 'मेक इन इंडिया' योजना के लिए कहा गया कि यह नौकरियों के सृजन में बढ़ोतरी करेगी लेकिन इसका कोई खास नतीजा सामने नजर नहीं आया। भविष्य में विदेशी बाजारों पर ध्यान केंद्रित करके रोजगार के बेहतर अवसर लाए जा सकते हैं। निर्यात और मैन्युफैक्चरिंग की प्रक्रिया रुक-सी गई है। जब तक निर्यात नहीं बढ़ेगा तब तक मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं बढ़ेगा। नई सरकार को निर्माण, पर्यटन, टेक्सटाइल और कृषि उत्पादों जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भाजपा ने अपने घोषणापत्र में वादा किया था कि वह मध्यम आय वाले परिवारों के हाथों में अधिक नकदी और अधिक क्रय शक्ति सुनिश्चित करने के लिए आय कर में कटौती करेगी। हालांकि सरकार की वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह तुरंत संभव नहीं हो सकता है। भारत का वित्तीय घाटा 3.4 फीसद पर है। यानी सरकारी व्यय और राजस्व के बीच का अंतर 3.4 फीसद है। ये आंकड़े सरकार के इस वादे की राह में रोड़ा साबित हो सकते हैं।

भारत में बढ़ता कृषि संकट भी सरकार के लिए उसके पहले कार्यकाल की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रहा है। मुल्क के किसान दिल्ली-मुंबई सहित देश के कई हिस्सों में सड़कों पर अपनी फसल के उचित दाम की मांग के साथ उतरे। हमें किसानों को स्वतंत्र माहौल देने की आवश्यकता है ताकि वे जिसे चाहें उसे अपने उत्पाद बेच सकें। यह उन्हें ऊंचे मूल्य वाली फसलों के उत्पादन के लिए भी प्रोत्साहित करेगा। भाजपा के चुनावी वादों में से एक यह था कि वह रेलवे, सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1.44 अरब डॉलर खर्च करेगी। लेकिन इतनी बड़ी रकम कहां से आएगी? जानकार मानते हैं कि सरकार इसके लिए निजीकरण की राह अपना सकती है। आने वाले दो साल सरकार के लिए सबसे बेहतर हैं जिनमें वह तेजी से निजीकरण अपना सकती है। भारत की नई, सहासिक और निर्भीक नीतियां विदेशी निवेशकों को निवेश करने के लिए लुभा सकती हैं। इन उपायों द्वारा एक मजबूत अर्थव्यवस्था अस्तित्व में आ सकती है जो सरकार को मिले विशाल जनादेश को सही अर्थों में सार्थक करेगी।

● *संजीव कुमार, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश*

इंसानियत से दूर

सूरत अग्निकांड में मासूमों की चीत्कार महसूस कर-के रूह कांप जाती है। फिर भी एक प्रश्न दिमाग में अनायास ही कौंध जाता है कि जिस दृश्य को दूर से देख कर हमारा हृदय इतना द्रवित हुआ, उसे समीप से देखते हुए सैकड़ों लोगों के कदम मदद के लिए आगे क्यों नहीं बढ़े। वे रुके, जेब से मोबाइल निकाला और आनन-फानन में उसका वीडियो बना कर सबको भेज दिया! आखिर क्यों उनके हाथ मासूमों को बचाने के लिए नहीं बढ़े?

एक अकेला 'केतन' पूरी मानवता को कैसे बचाएगा? हमें अपने भीतर उस संवेदना को जगाना होगा जो ऐसी घटनाओं पर बहादुर 'केतन' बन कर मदद के लिए आगे आए और सच्चा भारतीय होने का कर्तव्य निभाए।

● *रूपाली सिंह, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश*

पेशकश के बजाय

लोकसभा चुनाव में बड़ी हार के बाद कांग्रेस के अनेक नेता अपने इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं, लेकिन वे सिर्फ पेशकश क्यों कर रहे हैं, इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? असल में वे इस्तीफा देना ही नहीं चाहते। इसी तरह आम आदमी पार्टी की नेता अलका लांबा 2020 में पार्टी छोड़ने की बात कर रही हैं। 2020 में क्यों पार्टी छोड़ेंगी; अभी छोड़ने में क्या समस्या है या कोई प्रोटोकॉल है या 2020 में कोई बॉन्ड 'मैच्योर' होगा तब इस्तीफा देंगी? वे पार्टी की नीतियों से सहमत नहीं हैं तो घुट-घुट कर क्यों उसमें रहना चाहती हैं? यह भी एक दिखावा है। राहुल गांधी को भी इस्तीफा देना है तो किस बात का इंतजार कर रहे हैं? शायद पार्टी द्वारा खुशामद का इंतजार कर रहे हैं। कमलनाथ भी प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने को आतुर हैं, लेकिन दे नहीं रहे! कुछ इंतजार है! दरअसल, कोई इस्तीफा नहीं देने वाला। पद लोलुपता का त्याग करने की सबमें हिम्मत नहीं।

● *सतप्रकाश सनोठिया, रोहिणी, दिल्ली*

चौपाल

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com